

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 255 बेमेतरा, रविवार 10 मई 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रुपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

शुभेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, पांच अन्य मंत्री भी मंत्रिमंडल में शामिल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आजादी के बाद पहली बार राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम मोदी ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को दंडवत प्रमाण किया। शुभेंदु अधिकारी के साथ इन पांच विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली हैं। इनमें शामिल हैं दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तिनिया, क्षुदीराम टुडु, निशिथ प्रमाणिक। शुभेंदु ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में कहा कि पश्चिम बंगाल में अब सोनार बांग्ला के नए दौर की आधिकारिक शुरुआत हो रही है। शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में भावना के वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं में से एक माखनलाल सरकार का अभिनंदन किया और उनसे आशीर्वाद लिया। 98 वर्ष की आयु में भी माखनलाल सरकार स्वतंत्रताोत्तर भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े शुरुआती जमीनी स्तर के नेताओं में से एक हैं।



मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुवेंदु अधिकारी को दी बधाई एवं शुभकामनाएं, कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल

पश्चिम बंगाल में विकास के नए युग की शुरुआत: साय

रायपुर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया, जब सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लंबे समय से परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रही जनता की आशाओं को नई दिशा मिली और पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का सपना साकार हुआ। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोलकाता



पहुँचकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी सहित शपथ लेने वाले सभी मंत्रिपरिषद सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह जनादेश केवल सरकार बदलने का नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में विकास, सुशासन और नई कार्यसंस्कृति की स्थापना का जनसंकल्प है।



है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्वास व्यक्त किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और डबल इंजन सरकार की शक्ति से पश्चिम बंगाल विकास की नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नई सरकार के माध्यम से राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे, किसानों को समृद्धि का नया मार्ग मिलेगा तथा मातृशक्ति को सशक्त और सुरक्षित वातावरण प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने विकास, पारदर्शिता और सुशासन के पक्ष में अपना स्पष्ट विश्वास व्यक्त किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दो राज्यों में एक साथ नौकरी करने वाले सिपाही की बर्खास्तगी को सही माना

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उस सिपाही की बर्खास्तगी के आदेश को सही करार दिया है, जिसने झारखंड पुलिस से दो दिनों की छुट्टी लेकर जाली पहचान के साथ बिहार पुलिस में नौकरी हासिल कर ली थी। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी सिपाही रंजन कुमार को सेवा से बर्खास्त करने के अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश को खारिज कर दिया गया था। अदालत के अनुसार, कामता सिंह के पुत्र रंजन कुमार को 18 मई 2005 को झारखंड पुलिस में सिपाही के रूप में नियुक्त किया गया था। धुरकी पुलिस स्टेशन में रिजर्व गार्ड के रूप में सेवा करते समय उसे 20 दिसंबर 2007 से 22



दिसंबर 2007 तक दो दिनों की क्षतिपूर्क छुट्टी दी गयी थी। हालांकि वह 23 दिसंबर को इयूटी पर नहीं लौटा और बिना सूचना के अनुपस्थित रहा। जांच में पाया गया कि इसी अनुपस्थिति के दौरान, रंजन कुमार ने 26 दिसंबर 2007 को बिहार में 'संतोष कुमार पिता कामता शर्मा' के नाम से और जाली प्रमाणपत्रों व फर्जी दस्तावेजों के

आधार पर सिपाही की नौकरी हासिल कर ली थी। इसके बाद उसने छह जनवरी 2008 को बिना किसी अनुमति के पटना जिला पुलिस की इयूटी भी छोड़ दी। सीनियर एसपी पटना और एसपी जहानाबाद की कारायी गयी जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि रंजन कुमार और संतोष कुमार वास्तव में एक ही व्यक्ति थे। झारखंड पुलिस की विभागीय जांच में धोखाधड़ी, प्रतिरूपण (इम्पर्सनेशन), जालसाजी, धोखाधड़ी, इयूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति और सेवा अनुशासन के उल्लंघन के आरोप साबित हुए। शीर्ष अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सेवाओं में इस तरह की धोखाधड़ी और अनुशासनहीनता के लिए कोई स्थान नहीं है।

अनेक सामरिक लक्ष्यों पर निशाना लगाने वाली उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल उड़ान-परीक्षण

नयी दिल्ली। भारत ने अनेक सामरिक लक्ष्यों पर एक साथ निशाना लगाने वाली उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल उड़ान-परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह परीक्षण ओडिशा के डॉ एंथोनी अब्दुल कलाम द्वीप से बहु-स्वतंत्र लक्षित वाहन (एमआईआरवी) प्रणाली से किया। यह उड़ान-परीक्षण अनेक पेलोड के



साथ किया गया, जिन्हें हिन्द महासागर क्षेत्र में विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में स्थानिक रूप से फैले विभिन्न लक्ष्यों पर निर्देशित किया गया था। परीक्षण की टेलीमेट्री और ट्रैकिंग अनेक भू-आधारित तथा पोत-आधारित स्टेशनों द्वारा की गई। इन प्रणालियों ने प्रक्षेपण से लेकर सभी पेलोड के प्रभाव तक मिसाइल की पूरी उड़ान-पथ पर नजर रखी।

ममता के नेतृत्व में बिना डरे अपनी लड़ाई जारी रखेगी तृणमूल कांग्रेस : अभिषेक

नयी दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को कहा कि पार्टी ममता बनर्जी के नेतृत्व में बिना डरे और बिना किसी समझौते के अपनी लड़ाई जारी रखेगी। अभिषेक ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक पोस्ट में पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया की तीखी आलोचना करते हुए बड़े पैमाने पर मतदाताओं को वोट देने से रोकने, संवैधानिक अधिकारियों के पक्षपातपूर्ण व्यवहार

तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव के बाद हिंसा का आरोप लगाया। उन्होंने वा किया कि लगभग 30 लाख असली मतदाताओं को कथित तौर पर मतदाता सूची से हटा दिया गया था, जिसे उन्होंने बहुत मुश्किल चुनाव बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत चुनाव आयोग के साथ-साथ कई सरकारी एजेंसियों ने पूरे चुनाव के दौरान बहुत ज्यादा पक्षपातपूर्ण व्यवहार दिखाया।

ब्रिटेन के चुनाव परिणामों से सतारूढ़ लेबर पार्टी का जनाधार खोने का मिला संकेत

लंदन। ब्रिटेन में सात मई को 136 क्षेत्रों में नगर परिषदों की लगभग 5,000 सीटों के लिए चुनाव हुए। देश में अभी भी कुछ वोटों की गिनती जारी है लेकिन एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की लेबर पार्टी को भारी झटका लगा है। स्कॉटलैंड और वेल्स में क्रमशः 129 और 96 संसदीय सीटों पर एक ही दिन चुनाव हुए। वर्ष 2024 के बाद से यह सबसे बड़ा चुनाव रहा है और इसे व्यापक रूप से स्टारमर के प्रधानमंत्रित्व काल की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। निगेल फराज के नेतृत्व वाली रिफॉर्म यूके को चुनावों का सबसे बड़ा विजेता माना जा रहा है। स्काई न्यूज के अनुसार, इसने अब तक 1,422 सीटें जीती हैं। लेबर पार्टी 980 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि लिबरल डेमोक्रेट्स और कंजरवेटिव पार्टी क्रमशः 834 और 754 सीटों के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। प्लाइड सिमर, जो वेल्स की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध एक मध्य-वामपंथी पार्टी है।

गरीबी नहीं रोक सकी हौसले की उड़ान, 4 बार मेन्स, 3 बार इंटरव्यू, देशभर में हासिल की 91वीं रैंक तैदूपत्ता तोड़ने वाला लड़का बना आईएफएस अफसर

रायगढ़। सुबह की पहली किरण जैसे ही रायगढ़ जिले के संबलपुरी गांव की पगडंडियों पर उतरती थी, एक परिवार जंगल की ओर निकल पड़ता था। उस परिवार के साथ एक दुबला-पतला लड़का भी चलता जो कभी तैदूपत्ता तोड़ता, कभी महुआ बीनता। उसे तब शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन यही जंगल उसकी पहचान बन जाएगा। उस लड़के का नाम था, अजय गुप्ता। आज वही अजय गुप्ता भारतीय वन सेवा (IFS) परीक्षा में पूरे देश में 91वाँ रैंक हासिल कर चुका है। जिस जंगल से कभी उसके परिवार का चूल्हा जलता था, अब उसी जंगल की हिफाजत की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आने वाली है। यह सिर्फ अजय गुप्ता की सफलता की कहानी नहीं है,



यह कहानी ग्रामीण अंचलों के कच्ची मिट्टी के घर में बसते संघर्ष की है, जहां तमाम अभावों के बाद भी सपने जिंदा रहते हैं। अजय गुप्ता का बचपन बेहद कठिन परिस्थितियों में बीता। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि बड़े सपने देखे जा सकें। घर कच्ची मिट्टी और खपरैल का था। छत के बीच से आती धूप की किरणें ज़िंदगी में कभी-कभी उम्मीद की रोशनी भर

देती थीं। परिवार साल के छह महीने खेती करता और गर्मी के मौसम में जंगलों से तैदूपत्ता तोड़कर गुजारा करता था। दो जून की रोटी जुटाने के लिए पूरे परिवार को हाड़तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। गर्मी की छुट्टी के दिनों सुबह होते ही अजय भी अपने माता-पिता के साथ जंगल निकल जाते थे। अजय का बचपन तैदूपत्ता तोड़ने, महुआ बीनने और खेती किसानों के मौसम में खेतों में काम करते हुए बीतता। इस संघर्षों के बीच भी उनके माता-पिता ने एक सपना कभी मरने नहीं दिया। वह सपना था, अपने बच्चों की पढ़ाई का, माता-पिता निश्चय थे, मगर शिक्षा की ताकत को समझते थे। ज़िंदगी भर जो कमाया, उससे परिवार का पेट भी भरा और बच्चों की पढ़ाई भी चलती रही।



चंडीगढ़। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को पंजाब के उद्योग एवं बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित आवास पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान ईडी अधिकारियों के करीब 100 लोगों के आवास पर छापेमारी की गई। वहीं, छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज फिर से भाजपा की ईडी संजीव अरोड़ा के घर आई है।

अरोड़ा से जुड़े कई घरों और कार्यस्थलों पर छापेमारी की थी। गौरतलब है कि यह कार्रवाई खरडू के वेस्टर्न टावर्स में कथित संपर्क एजेंट नितिन गोहल के आवास पर हुई ईडी की छापेमारी के बाद सामने आई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज फिर से भाजपा की ईडी संजीव अरोड़ा के घर आई है।

कैसे बदली ज़िंदगी?

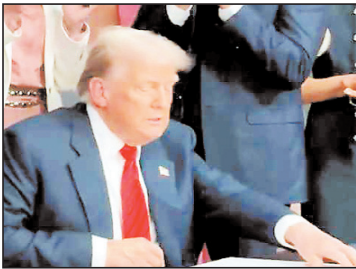
अजय पढ़ाई में शुरू से ही बेहद मेधावी रहे। साल 2011 में उन्होंने 10वीं कक्षा में 93 प्रतिशत अंक हासिल किए। यह उनके जीवन का बड़ा मोड़ साबित हुआ। तैदूपत्ता संग्राहक परिवारों के बच्चों के लिए सरकार ने छात्रवृत्ति योजना शुरू की थी। अजय को इस योजना का लाभ मिला और आगे की पढ़ाई का रास्ता आसान हुआ। उन्होंने 12वीं कक्षा में भी शानदार प्रदर्शन किया और इसके बाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर में प्रवेश मिला। एनआईटी में पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने तीन वर्षों तक छात्रवृत्ति मिलती रही। अजय कहते हैं- पहले सपने बहुत बड़े नहीं थे। लगता था कि हमारी

दुनिया बस गांव तक सीमित है, लेकिन एनआईटी में एडमिशन लेने के बाद नजरिया बदल गया। पहली बार लगा कि मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं।

नौकरी मिली, लेकिन मन कुछ और चाहता था

एनआईटी में पढ़ाई के दौरान ही अजय को कैम्पस प्लेसमेंट मिला। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह बस्तर में काम कर रही संस्था 'प्रदान' से जुड़ गए। यहाँ उन्होंने आदिवासी समुदायों के बीच चार वर्षों तक काम किया। लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में काम करते हुए उन्होंने आदिवासियों के जीवन और जंगल के रिश्ते को बेहद करीब से समझा।

ट्रम्प ने रूस-यूक्रेन के बीच तीन दिवसीय युद्धविराम 1,000 कैदियों की अदला-बदली की घोषणा की



यह अस्थायी युद्धविराम नौ मई से 11 मई तक रहेगा और यह चार साल से अधिक समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में जारी राजनयिक प्रयासों के बीच हुआ है। ट्रम्प की घोषणा के कुछ ही समय बाद, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लाडिमिर ज़ेलेन्स्की ने पुष्टि किया कि यूक्रेन युद्धविराम में शामिल होगा। रूसी सरकारी मीडिया ने भी कहा कि रूस ने

प्रवर्तन निदेशालय ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित आवास पर की छापेमारी

चंडीगढ़। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को पंजाब के उद्योग एवं बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित आवास पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान ईडी अधिकारियों के करीब 100 लोगों के आवास पर छापेमारी की गई। वहीं, छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज फिर से भाजपा की ईडी संजीव अरोड़ा के घर आई है।

लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि नये प्रमुख रक्षा अध्यक्ष वाइस एडमिरल स्वामीनाथन नये नौसेना प्रमुख नियुक्त

नयी दिल्ली। लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि (सेवानिवृत्त) को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) और वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों में इन महत्वपूर्ण नियुक्तियों की शनिवार सुबह घोषणा की।



लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणि जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका 30 मई को कार्यकाल पूरा हो रहा है जबकि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह नौसेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगे जो 31 मई को सेवा निवृत्त हो रहे हैं। ले जनरल

सुब्रमणि सैन्य कार्य विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे और उनकी नियुक्ति उनके कार्यभार संभालने के दिन से प्रभावी मानी जायेगी और वह अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणि एक सितंबर 2025 से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले वह 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक सेना के उप प्रमुख रहे तथा मार्च 2023 से जून 2024 तक केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ रहे।

पीएम मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना जायेंगे, हैदराबाद में 9400 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक और तेलंगाना की यात्रा पर जायेंगे जहां वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपये की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मोदी सुबह 11 बजे बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह और रवि शंकर के 70वें जन्मदिवस समारोह में भाग लेंगे। वह बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग अंतरराष्ट्रीय केंद्र में नव-निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे, जो आंतरिक शांति और समग्र कल्याण के लिए समर्पित एक ध्यान कक्ष है। वह संगठन की राष्ट्रव्यापी सेवा पहलों का भी शुभारंभ करेंगे, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, प्रकृति संरक्षण और सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित वर्षभर चलने वाली परियोजनाएँ शामिल हैं। वह इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जाएंगे और लगभग तीन बजे लगभग 9,400 करोड़ रुपये की अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।



प्रधानमंत्री कल गुजरात जायेंगे, सोमनाथ अमृत महोत्सव में होंगे शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार से दो दिन के गुजरात दौरे पर जायेंगे, जहां वह सोमनाथ मंदिर में 'सोमनाथ अमृत महोत्सव' में भाग लेंगे। मोदी रविवार देर रात गुजरात के जामनगर पहुंचेंगे और सोमवार को सुबह सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। इसके बाद वह वडोदरा जाएंगे, जहां वह लगभग शाम छह बजे सरदारधाम हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे। वह दोनों अवसरों पर जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। पवित्र सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और भारत की शाश्वत आस्था तथा सभ्यतागत विरासत का प्रतीक है।

[illegible]

संपादकीय

कहा जा सकता है कि इन चुनावों में भाजपा ने जहां पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में जीत हासिल कर अपनी उपस्थिति साबित की है, वहीं कांग्रेस भी केरल की जीत को अपनी बड़ी उपलब्धि बता सकती है।चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के जैसे नतीजे सामने आए हैं, उनसे साफ है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में जहां मतदाताओं ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया, वहीं असम और पुदुचेरी में लोगों ने मौजूदा सरकार पर भरोसा कायम रखा। इसमें चौंकाने वाले नतीजे

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से आए, जहां चुनाव प्रचार के क्रम में बहुस्तरीय उताव-चढ़ाव के बावजूद लोगों के लिए यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि सत्ताधारी पार्टियों का प्रदर्शन बेहद कमजोर हो सकता है। इन राज्यों में इतने बड़े उलटफेर की उम्मीद कम ही लोगों ने की थी।दरअसल, पश्चिम बंगाल में तुणमूल कांग्रेस की सरकार के प्रति दिखने वाला जनसमर्थन चुनाव और मतदान के मोर्चे पर उलट नतीजे देने वाला साबित हुआ। हालांकि राज्य में भाजपा ने जीत के लिए जिस स्तर पर जाकर मेहनत की,

मतदाताओं के वोट अपने पक्ष में लाने के लिए एक व्यापक रणनीतिक राजनीति पर काम किया और यहां तक भावनात्मक मुद्दों का भी सहारा लिया, उसका साफ असर मतगणना और नतीजों पर दिखा। जाहिर है, लंबे समय के बाद अब पश्चिम बंगाल एक और सत्ता परिवर्तन का गवाह बन रहा है, जहां विचारधाराओं का सफर क्रमशः बदलता दिखा है।वहीं तमिलनाडु में एमके स्टालिन के नेतृत्व वाले द्रविड़ मुनेत्र कडगम (द्रमुक) को लेकर बहुत कम लोगों ने यह अंदाजा लगाया होगा कि चुनाव के परिणाम में

उसकी स्थिति इस कदर खराब रहेगी। गौरतलब है कि फिल्मों की दुनिया से तमिलनाडु की राजनीति में आकर हाल के वर्षों में उभरे और अपने प्रशंसकों के बीच थलापित के नाम से मशहूर जोसेफ विजय ने अपने पहले ही चुनाव में राज्य की राजनीति में बीते कुछ सालों से एकछत्र राज करने वाले नेता एमके स्टालिन और उनकी पार्टी द्रमुक को करारी शिकस्त दी। अब तमिलनाडु द्रमुक और अन्नाद्रमुक के इर्द-गिर्द घूमने वाली राजनीति के समांतर एक नए दौर में प्रवेश कर गया है। यह देखने की बात होगी कि

आने वाले वर्षों में यह राज्य किस राजनीतिक धारा का केंद्र बनेगा।जहां तक केरल का सवाल है, तो वहां आमतौर पर वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड लोकतांत्रिक मोर्चे के बीच सत्ता में फेरबदल होता रहा है। इस लिहाज से देखें तो दो कार्यकाल के बाद वामपंथी मोर्चा सत्ता से बाहर हुआ है और अच्छी उपस्थिति के साथ कांग्रेस को महत्त्वपूर्ण जीत मिली है।इसके अलावा, असम में एक तरह से अपेक्षित नतीजे आए हैं, जहां भाजपा ने फिर से भारी जीत हासिल की है। यह

तब भी संभव हुआ, जब राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के रुख को लेकर कई तरह के विवाद चुनाव प्रचार के केंद्र में रहे। इसी तरह, केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी के परिणामों के मुताबिक, वहां सत्तारूढ़ राजग गठबंधन ने एक बार फिर बहुमत हासिल कर अपनी सत्ता कायम रखी।कहा जा सकता है कि इन चुनावों में भाजपा ने जहां पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में जीत हासिल कर अपनी उपस्थिति साबित की है, वहीं कांग्रेस भी केरल की जीत को अपनी बड़ी उपलब्धि बता सकती है।

हादसे का इंतजार नहीं कर सकती सरकार, परस्पर पूरक हैं धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हाईकोर्ट के दो हालिया फैसले

दूसरे फैसले में अदालत ने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर सबका समान अधिकार है, और निजी स्थल पर भी धार्मिक स्वतंत्रता असीमित नहीं है। यदि कोई गतिविधि सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने लगे तो उसे नियंत्रित करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। सरकार लोक व्यवस्था के छिन्न-भिन्न होने का इंतजार नहीं कर सकती। ये दोनों फैसले विरोधाभासी नहीं हैं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं और मिलकर उस व्यवस्था को रेखांकित करते हैं जिसके भीतर एक लोकतांत्रिक, बहुलवादी समाज में धर्म और कानून को साथ-साथ चलना होता है। इस न्यायिक दृष्टिकोण ने इस मूल सिद्धांत को रेखांकित किया है कि किसी भी नागरिक या समूह का अधिकार तभी तक सुरक्षित है, जब तक वह दूसरे नागरिकों के अधिकारों, सार्वजनिक व्यवस्था और सामूहिक हितों से टकराव नहीं पैदा करता।

(रितिका सिंह सिसोदिया) एक माह के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो फैसले, दो अलग-अलग समय में आए, लेकिन दोनों को मिलाकर पढ़ें तो एक स्पष्ट और संतुलित संवैधानिक दर्शन उभरकर सामने आता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उसमें अधिकार भी हैं और उन अधिकारों की सीमाएं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। एक माह के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो फैसले, दो अलग-अलग समय में आए, लेकिन दोनों को मिलाकर पढ़ें तो एक स्पष्ट और संतुलित संवैधानिक दर्शन उभरकर सामने आता है।

पहले फैसले में अदालत ने कहा था कि नमाजियों की संख्या सीमित करना गलत है, कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

दूसरे फैसले में अदालत ने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर सबका समान अधिकार है, और निजी स्थल पर भी धार्मिक स्वतंत्रता असीमित नहीं है। यदि कोई गतिविधि सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने लगे तो उसे नियंत्रित करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। सरकार लोक व्यवस्था के छिन्न-भिन्न होने का इंतजार नहीं कर सकती। ये दोनों फैसले विरोधाभासी नहीं हैं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं और मिलकर उस व्यवस्था को रेखांकित करते हैं जिसके भीतर एक लोकतांत्रिक, बहुलवादी समाज में धर्म और कानून को साथ-साथ चलना होता है।

इस न्यायिक दृष्टिकोण ने इस मूल सिद्धांत को रेखांकित किया है कि किसी भी नागरिक या समूह का अधिकार तभी तक सुरक्षित है, जब तक वह दूसरे नागरिकों के अधिकारों, सार्वजनिक व्यवस्था और सामूहिक हितों से टकराव नहीं पैदा करे।। यह केवल एक कानूनी व्याख्या नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक चेतना का संकेत है, जो यह बताता है कि आधुनिक राज्य व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक हितों के बीच संतुलन बनाकर ही चल सकती है।

सबसे पहले संभल के मूल विवाद को समझते हैं। यह विवाद एक ऐसी भूमि से संबंधित है जिसे याचिकाकर्ता अपनी निजी भूमि बताता है और उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वहां नमाज अदा करने के लिए परमादेश जारी करने की मांग की थी। प्रारंभ में जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया था कि एक विशेष परिसर में नमाजियों की संख्या को सीमित किया जाए। आधार यह था कि भीड़ बढ़ने से कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। यह प्रशासनिक दृष्टिकोण एहतियात और व्यवस्था बनाए रखने की भावना से प्रेरित था, लेकिन इस आदेश को चुनौती देते हुए मामला न्यायालय तक पहुंचा।

न्यायापालिका ने अपने पहले निर्णय में कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य का मूल दायित्व है। न्यायालय के उस आदेश का भावार्थ यह था कि यदि प्रशासन यह मान ले कि किसी धार्मिक गतिविधि के कारण स्वाभाविक रूप से व्यवस्था बिगड़ सकती है, और उसी आधार पर प्रतिबंधात्मक कदम उठाए जाएं, तो यह दृष्टिकोण संविधान की भावना के विपरीत होगा।

लेकिन इस पूरे विवाद का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसे बाद में न्यायालय के एक अन्य निर्णय में अधिक स्पष्टता के साथ सामने रखा गया। इस दूसरे दृष्टिकोण ने सार्वजनिक भूमि, निजी संपत्ति और धार्मिक गतिविधियों के बीच संतुलन

है कि संविधान व्यक्ति की आस्था और निजी जीवन की स्वतंत्रता को पूर्ण संरक्षण देता है, लेकिन इस संरक्षण की एक सीमा भी है। यह केवल तब तक लागू है जब तक गतिविधि वास्तव में निजी और सीमित बनी रहती है।

संभल विवाद के संदर्भ में यही प्रश्न केंद्रीय था कि क्या किसी निजी या सीमित स्थान पर होने वाली गतिविधि धीरे-धीरे सार्वजनिक स्वरूप ग्रहण कर रही थी?

न्यायालय ने इस पहलू को अत्यंत व्यावहारिक दृष्टि से देखा और कहा कि जैसे ही कोई गतिविधि 'सामूहिक चरित्र' ग्रहण करती है, वह केवल आंतरिक आस्था का विषय नहीं रह जाती।

अदालत के शब्दों में, 'एक बार जब गतिविधि ऐसा सामूहिक चरित्र ग्रहण कर लेती है, तो यह केवल आंतरिक आस्था का मामला नहीं रह जाता।' इस परिवर्तन के साथ ही उसके प्रभाव भी व्यापक हो जाते हैं। प्रवेश और निकास से लेकर यातायात और पार्किंग संबंधी चिंताएं पैदा हो सकती हैं, इलाके का चरित्र बदल सकता है, शोर उत्पन्न हो सकता है, पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता हो सकती है और संवेदनशील क्षेत्रों में, अंतर-समुदाय तनाव की आशंका पैदा कर सकती है।

ऐसी स्थिति में गतिविधि 'एक सार्वजनिक या अर्ध-सार्वजनिक आयाम ग्रहण कर लेती है।' यहां यह भी देखा होगा कि प्रकरण ऐसे जिले का है जो कुछ समय पहले सांप्रदायिक विमर्श के केंद्र में था, जहां धार्मिक तनाव की आग भड़क चुकी है और सड़कों पर खून बह चुका है। कोर्ट की अवधारणा स्पष्ट है कि अधिकार केवल घोषित नहीं होते, उनका प्रभाव भी उनकी प्रकृति निर्धारित करता है। यदि प्रभाव

‘ऐसा नहीं है कि निजी संपत्ति सभी संरक्षण खो देती है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था के प्रभावित होने की स्थिति में ऐसी संपत्ति का उपयोग विशुद्ध रूप से निजी नहीं रह जाता और उचित विनियमन के अधीन हो जाता है।’

यह कथन शासन और प्रशासन के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि अधिकारों का उपयोग सामाजिक प्रभाव से अलग नहीं देखा जा सकता। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में शासन-प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रशासन का दायित्व केवल कानून लागू करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि किसी भी गतिविधि से समाज में असंतुलन न पैदा होे। यही कारण है कि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई गतिविधि कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने की संभावना रखती है, तो राज्य को हस्तक्षेप का पूरा अधिकार है।

संभल का यह विवाद अंततः हमें एक व्यापक सिद्धांत की ओर ले जाता है कि लोकतंत्र केवल अधिकारों का संग्रह नहीं है, बल्कि संतुलित जिम्मेदारियों का ढांचा है। यह ढांचा तभी मजबूत रहता है जब प्रत्येक अधिकार अपने दायरे में सीमित रहे और किसी दूसरे के अधिकार को प्रभावित न करे। यही संतुलन संभल विवाद को केवल एक स्थानीय मुद्दे से ऊपर उठाकर एक व्यापक संवैधानिक और सामाजिक विमर्श में बदल देता है और यही इस पूरे प्रसंग का सबसे स्थायी संदेश है कि विधि का शासन तभी जीवित रहता है जब अधिकार, कर्तव्य और प्रशासनिक विवेक एक साथ संतुलित रूप में कार्य करें।

पश्चिम बंगाल में भाजपा की चली सुनामी के सियासी मायने दूरगामी महत्त्व वाले

(कमलेश पांडे) पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत केवल सरकार बदलने की घटना नहीं होगी, बल्कि यह भारतीय राजनीति में ‘पूर्वी भारत के वैचारिक परिवर्तन’ का प्रतीक मानी जाएगी। इससे विपक्ष का शक्ति-संतुलन बदलेगा, भाजपा का राष्ट्रीय आत्मविश्वास बढ़ेगा और बंगाल की दशकों पुरानी राजनीतिक संस्कृति में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र में विगत बारह वर्षों से सत्तारूढ़ ‘भारतीय जनता पार्टी’ ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में निर्णायक जीत दर्ज करके जनसंघ के संस्थापक और बंगाल मूल के दूरदर्शी हिंदूवादी राजनेता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अद्भुत श्रद्धांजलि दी है। सच कहूं तो आरएसएस के इस सुप्रसिद्ध सिपाही का कश्मीर में दिया हुआ सियासी बलिदान व्यर्थ नहीं गया। खासकर यह उपलब्धि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर भाजपा द्वारा उसे दिया हुआ बहुमूल्य वैचारिक तोहफा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत केवल सरकार बदलने की घटना नहीं होगी, बल्कि यह भारतीय राजनीति में ‘पूर्वी भारत के वैचारिक परिवर्तन’ का प्रतीक मानी जाएगी। इससे विपक्ष का शक्ति-संतुलन बदलेगा, भाजपा का राष्ट्रीय आत्मविश्वास बढ़ेगा और बंगाल की दशकों पुरानी राजनीतिक संस्कृति में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है। कम शब्दों में कहा जाए तो भय हारा और भरोसा जगा है। बदलोक के हृदय परिवर्तन से सोनार बंगला के बहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिलने से हिंदुओं का मनोबल बढ़ेगा और बंगलादेशी घुसपैठियों से देश को मुक्ति मिलेगी।

इस शुभ घड़ी को दिखलाने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, भाजपा के राष्ट्रीय अध्ययन नितिन नवीन की सूझबूझ और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सियासी तैवरों का

भी अहम योगदान है। वहीं, हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेताओं उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व सरमा के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं, पश्चिम बंगाल के राजनेता सुवेन्दु अधिकारी, दिलीप बोस जैसे कर्मठ नेताओं और भाजपा के ‘बलिदानी’ कार्यकर्ताओं के अथक संघर्ष का प्रतिफल है।

देखा जाए तो यह भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं और उनका हैसलाअफ़जई करते रहने वाले स्थानीय और बाहरी नेताओं के संयुक्त प्रयासों का सकारात्मक नतीजा है, जिसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं। बंगलादेश की हिन्दू विरोधी मानसिकता और ग्रेटर बंगलादेश की थ्योरी ने पूर्वी भारत के हिंदुओं को इस कदर भयभीत कर दिया है कि अब उनके पास भाजपा के नेतृत्व में गोलबंद होने के अलावा कोई चार नहीं बचा था। लिहाजा, पहले कलिंग यानी उड़ीसा, फिर अंग यानी बिहार और अब बंग यानी पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत और भगवा की बुलंदी बहुत कुछ राजनीतिक चुगली करती है, जिसे समझने, और जनमानस को समझाने की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर में बसे पूर्वी भारत के कर्तव्यनिष्ठ आरएसएस/भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं की मानें तो यह उनके सामूहिक प्रयासों की विजय हैजो अनवरत रूप से जारी अथक जनसंघर्षों और कार्यकर्ताओं के बलिदानों की वजह से मिली है। लिहाजा इसके राजनीतिक निहितार्थ केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति, संघीय ढांचे और विपक्ष की रणनीति पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। वहीं, निकट भविष्य में पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया तक में इसकी अनुगुं सुनाई पड़ेगी।

लिहाजा, इस अभूतपूर्व विजय के प्रमुख राजनीतिक निहितार्थ/मायने इस प्रकार होंगे: 1. पूर्वी भारत में भाजपा का निर्णायक विस्तार

पश्चिम बंगाल लंबे समय तक वामपंथ और बाद में

ऑल इंडिया तुणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहां भाजपा की जीत यह संकेत देगी कि पार्टी अब हिंदी पट्टी से आगे निकलकर पूर्वी भारत में स्थायी राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। इससे ओडिशा, असम और पूर्वोत्तर में भाजपा की पकड़ और मजबूत होगी। अन्य राज्यों में विस्तार भी होगा।

2. ममता बनर्जी की राष्ट्रीय भूमिका कमजोर पड़ना: ममता बनर्जी विश्वेश्वी राजनीति की सबसे आक्रामक नेताओं में मानी जाती रही हैं। बंगाल में हार होने पर उनकी ‘राष्ट्रीय विकल्प’ वाली छवि को गहरा झटका लगेगा। इंडिया गठबंधन की राजनीति में उनका प्रभाव कम हो सकता है और विपक्ष का नेतृत्व पुनः बिखर सकता है। जबकि राहुल गांधी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि उनकी टांग खींचने वाले सारे क्षेत्रीय नेता उनकी सटीक रणनीति से सियासी धूल फांकने को अभिशप्त हुए। इससे भविष्य में कांग्रेस लाभान्वित होगी।

3. कांग्रेस और वामपंथ का लगभग राजनीतिक अंत: पश्चिम बंगाल में पहले ही चुनाव भाजपा बनाम तुणमूल तक सिमटता दिख रहा है। भाजपा की जीत होने पर यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस और वामदलों की पारंपरिक राजनीति बंगाल में अप्रासंगिक हो चुकी है।

4. ‘हिंदुत्व और कल्याणकारी राजनीति’ मॉडल की सफलता: भाजपा ने बंगाल में राष्ट्रवाद, सीमा सुरक्षा, घुसपैठ, नागरिकता और हिंदू पहचान के मुद्दों को कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़कर चुनावी रणनीति बनाई है। यदि यह सफल होती है, तो पार्टी इस मॉडल को अन्य राज्यों में भी और आक्रामक रूप से लागू करेगी।

5. बंगाल की राजनीतिक संस्कृति में बड़ा बदलाव: बंगाल लंबे समय तक वैचारिक राजनीति, वामपंथी विमर्श और क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति के लिए जाना जाता रहा है। भाजपा की जीत यह संकेत देगी कि बंगाल की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुकीं से

ऑल इंडिया तुणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहां भाजपा की जीत यह संकेत देगी कि पार्टी अब हिंदी पट्टी से आगे निकलकर पूर्वी भारत में स्थायी राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। इससे ओडिशा, असम और पूर्वोत्तर में भाजपा की पकड़ और मजबूत होगी। अन्य राज्यों में विस्तार भी होगा।

2. ममता बनर्जी की राष्ट्रीय भूमिका कमजोर पड़ना: ममता बनर्जी विश्वेश्वी राजनीति की सबसे आक्रामक नेताओं में मानी जाती रही हैं। बंगाल में हार होने पर उनकी ‘राष्ट्रीय विकल्प’ वाली छवि को गहरा झटका लगेगा। इंडिया गठबंधन की राजनीति में उनका प्रभाव कम हो सकता है और विपक्ष का नेतृत्व पुनः बिखर सकता है। जबकि राहुल गांधी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि उनकी टांग खींचने वाले सारे क्षेत्रीय नेता उनकी सटीक रणनीति से सियासी धूल फांकने को अभिशप्त हुए। इससे भविष्य में कांग्रेस लाभान्वित होगी।

3. कांग्रेस और वामपंथ का लगभग राजनीतिक अंत: पश्चिम बंगाल में पहले ही चुनाव भाजपा बनाम तुणमूल तक सिमटता दिख रहा है। भाजपा की जीत होने पर यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस और वामदलों की पारंपरिक राजनीति बंगाल में अप्रासंगिक हो चुकी है।

4. ‘हिंदुत्व और कल्याणकारी राजनीति’ मॉडल की सफलता: भाजपा ने बंगाल में राष्ट्रवाद, सीमा सुरक्षा, घुसपैठ, नागरिकता और हिंदू पहचान के मुद्दों को कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़कर चुनावी रणनीति बनाई है। यदि यह सफल होती है, तो पार्टी इस मॉडल को अन्य राज्यों में भी और आक्रामक रूप से लागू करेगी।

5. बंगाल की राजनीतिक संस्कृति में बड़ा बदलाव: बंगाल लंबे समय तक वैचारिक राजनीति, वामपंथी विमर्श और क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति के लिए जाना जाता रहा है। भाजपा की जीत यह संकेत देगी कि बंगाल की राजनीति में अप्रासंगिक संघर्ष से

निकलकर राष्ट्रीय ध्रुवीकरण और पहचान-आधारित राजनीति की ओर बढ़ रही है।

6. 2029 लोकसभा चुनाव की दिशा तय होगी: भाजपा द्वारा बंगाल जीत से 2029 लोकसभा चुनाव के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी। बंगाल की 42 लोकसभा सीटें राष्ट्रीय सत्ता संतुलन में बेहद महत्वपूर्ण हैं। भाजपा यह संदेश दे सकेगी कि उसका विस्तार अब दक्षिण और पूर्व भारत तक स्थायी रूप से हो चुका है।

7. संघ और भाजपा संगठन की रणनीति को वैधान्तः पश्चिम बंगाल में भाजपा का संगठन वर्षों तक कमजोर माना जाता था। यदि पार्टी सत्ता तक पहुंचती है, तो यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के दीर्घकालिक कैडर विस्तार मॉडल को बड़ी सफलता मानी जाएगी। सोशल और वैचारिक स्तर पर संघ की पैठ को भी मजबूती मिलेगी।

8. केंद्र-राज्य संबंधों में नया समीकरण: अब तक बंगाल और केंद्र सरकार के संबंध अक्सर टकरावपूर्ण रहे हैं। भाजपा सरकार बनने पर केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बढ़ेगा, जिससे निवेश, बुनियादी ढांचे और केंद्रीय परियोजनाओं को गति मिल सकती है। हालांकि विपक्ष इसे ‘संघीय ढांचे के केंद्रीकरण’ के रूप में भी प्रस्तुत कर सकता है।

9. पहचान और सुरक्षा राजनीति को बल: सीमा पार घुसपैठ, एनआरसी-सीएफ, बांग्लादेश सीमा और जनसंख्या के बदलाव जैसे मुद्दे बंगाल की राजनीति के केंद्र में आ जाएंगे। भाजपा की जीत इन मुद्दों को राष्ट्रीय बहस में और प्रमुख बना सकती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत केवल सरकार बदलने की घटना नहीं होगी, बल्कि यह भारतीय राजनीति में ‘पूर्वी भारत के वैचारिक परिवर्तन’ का प्रतीक मानी जाएगी। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक है।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

छोटे देवड़ा में 15वें वित्त की राशि पर घोटाले का आरोप, धरातल पर नाली अपूर्ण, पवन कुमार नाग संभागीय ब्यूरो चीफजिला बस्तर

बकावंड/मूक पत्रिका

विकासखण्ड बकावंड के ग्राम पंचायत छोटे देवड़ा में 15वें वित्त आयोग की राशि से कराए जाने वाले नाली निर्माण कार्य को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्षेत्रीय जनपद सदस्य ने पंचायत में वित्तीय अनियमितता और फर्जी भुगतान का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से तत्काल जांच की मांग की है।

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत छोटे देवड़ा में नाली निर्माण कार्य के लिए 15वें वित्त आयोग की मद से 2 लाख 17 हजार रुपये स्वीकृत किए गए थे। पंचायत के दस्तावेजों में नाली निर्माण कार्य का उल्लेख किया गया है, लेकिन ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि धरातल पर अब तक नाली निर्माण अधूरा है। कोई स्पष्ट कार्य दिखाई नहीं देता। मौके पर निर्माण कार्य नहीं होने के बावजूद राशि निकाले जाने का आरोप लगने से पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। क्षेत्रीय जनपद सदस्य ने

नगर पालिका परिषद सारंगढ़ का बड़ा फैसला: नियमों को ताक पर रखकर दी गई लीज निरस्त, अब चलेगा अतिक्रमण पर डंडा!

सारंगढ़/मूक पत्रिका

भ्रष्टाचार और नियम विरुद्ध बंदरबांट के खिलाफ सारंगढ़ नगर पालिका परिषद ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। नया तालाब पर स्थित बेशकीमती सरकारी जमीन को 'खैरात' में बांटने के पुराने फैसले को पलटते हुए पालिका ने लीज निरस्त कर दी है। अब गंद तहसीलदार के पाले में हैं, जिन्हें इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का जिम्मा सौंपा गया है।

क्या है पूरा मामला? मामला साल 2016 का है, जब नगर पालिका परिषद ने संकल्प क्रमांक 430 के जरिए मधुसूदन बानी (पिता नित्यानंद बानी) को उनके घर के पीछे की 10 डुहड़दहड़ा 41 वर्गफीट सरकारी जमीन 'अस्थायी लीज' पर दे दी थी। लेकिन जैसे ही यह मामला परिषद की नई कार्यप्रणाली के रडार पर आया, नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दीं।

जाते ही परिषद ने लिया 'यू-टर्न' परिषद ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका नियम 2016 की

'प्रयास' आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा कल: भीषण गर्मी को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर पेयजल और सुरक्षा के फुल्टा इंतजाम की मांग

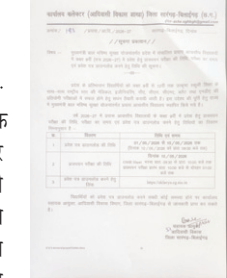
सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक

पत्रिका

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास शाखा) द्वारा जारी सूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 'प्रयास आवासीय विद्यालयों' में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा कल, 10 मई 2026 को आयोजित की जाएगी।

परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी:सरकारी पत्र के अनुसार परीक्षाओं और अभिभावक इन समय-सीमाओं का विशेष ध्यान रखें:प्रवेश पत्र डाउनलोड: वेबसाइट https://eklavya.cg.nic.in से कल सुबह 09:30 बजे तक प्रवेश पत्र निकाले जा सकते हैं।

परीक्षा का समय: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक।



आया है। अब नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (ष्ट्रुक्) ने तहसीलदार को सख्त लहजे में पत्र लिखकर इस भूखंड का सीमांकन करने और इसे अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया है।

बेबाक सवाल: आखिर जिम्मेदार कौन?

यह खबर केवल एक लीज निरस्त होने की नहीं है, बल्कि उन रसुखदरो के लिए चेतावनी है जो सरकारी जमीन को अपनी जागीर समझ बैठे हैं।

सवाल यह है कि 2016 में किस दबाव या सांठागंट के तहत यह लीज दी गई थी?

सवाल यह भी है कि जब मई 2025 में ही इसे निरस्त करने का निर्णय ले लिया गया था, तो अब तक सरकारी जमीन पर कब्जा क्यों बरकरार है?

माटी के संदेश की नजर अब इस कार्रवाई पर टिकी है। क्या प्रशासन बिना किसी रसुख के दबाव में आए इस कीमती भूमि को मुक्त करा पाएगा या फइलें फिर से धूल फेंकने लगेंगी?

नौकरी दिलाने' के नाम पर 3.38 लाख की ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र देकर

युवती को बनाया शिकार, रायगढ़ पुलिस ने आरोपी को जशपुर से दबोचा

एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश : नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे मांगने वाले ऐसे तत्वों पर भरोसा न करें, केवल अधिकृत माध्यमों पर ही विश्वास करें

रायगढ़/मूक पत्रिका

कलेक्ट्रेट सारंगढ़ में कम्प्यूटर ऑपरेटर की नौकरी लगवाने का झांसा देकर 3 लाख 38 हजार 500 रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी हरीश मिश्रा को थाना कोतरारोड़ पुलिस ने प्यारी के दौरान जिला जशपुर से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी ने पीड़िता को सविदा नियुक्ति दिलाने का भरोसा दिलाकर नकद और ऑनलाइन माध्यम से रकम



हासिल की थी तथा बाद में फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लंबे समय तक गुमराह करता रहा। जानकारी के अनुसार ग्राम कोतरा निवासी कुमारी पद्मिनी यादव (27 साल) ने दिनांक 03 अप्रैल 2026 को थाना कोतरारोड़ में लिखित शिकायत देकर बताया कि उसकी भतीजी के माध्यम से आरोपी हरीश मिश्रा से पहचान हुई थी। आरोपी ने कलेक्ट्रेट सारंगढ़ में कम्प्यूटर ऑपरेटर पद पर सविदा नियुक्ति कराने का भरोसा देकर अलग-अलग तरीकों में 09 फरवरी 2026 से 22 मार्च 2026 के बीच

रायगढ़/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। कर्मचारियों ने उस समय भारी आक्रोश व्यक्त हो गया जब श्रम सम्मान निधि पर दिसंबर 2025 से रोक लगा दी गई। वर्षों से निगम ने सेवाएं दे रहे कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें श्रम सम्मान निधि के रूप में मिलने वाली 4000 रुपए की राशि उनके परिवार के पालन-पोषण, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई एवं दैनिक जरूरतों का महत्वपूर्ण सहारा थी, लेकिन प्रबंधन द्वारा इस राशि पर रोक लगाकर कर्मचारियों को आर्थिक संकट में धकेल दिया गया है।दैनिक वेतनभोगी कर्मचारों संघ ने आरोप लगाया है कि एक ओर कर्मचारियों की मेहनत और अधिकारों की लगातार अनदेखी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रबंधन आउटसोर्सिंग के माध्यम से नए कर्मचारियों को भर्ती कराने की तैयारी कर रहा है। संघ ने सवाल उठाया है कि जब आउटसोर्स कर्मचारियों को



15 हजार से 17 हजार रुपए प्रतिमाह देने के लिए प्रबंधन के पास पर्याप्त बजट उपलब्ध है, तब वर्षों से कम वेतन में सेवा दे रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उचित वेतन एवं श्रम सम्मान निधि देने में आखिर समस्या क्या है? संघ ने यह भी आरोप लगाया कि हड़ताल को कमजोर करने एवं शासन को गुमराह करने के लिए बीज भंडारण की फर्जी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि प्रदेश की अधिकारिता समितियों में एक बोरी तक बीज का भंडारण नहीं हुआ है। कई स्थानों पर बीज उठाव, भंडारण एवं वितरण का कार्य पूरी तरह प्रभावित पड़ा हुआ है, लेकिन कागजों में सब कुछ सामान्य दर्शाया जा रहा है। अधिकारियों एवं प्रबंधकों पर दबाव बनाकर गलत रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है ताकि यह दिखाया जा

भारतीय डाक विभाग की इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा 10 लाख रुपए का भुगतान मटका निवासी माया यदु को

बेमेतरा /मूक पत्रिका

भारतीय डाक विभाग की इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बेमेतरा द्वारा बीते शनिवार को ग्राम पंचायत मटका में पोस्ट पेमेंट बैंक ऑफिस के द्वारा माया यदु पति स्वर्गीय नंदलाल यदु मटका निवासी को प्रति वर्ष 565रुपए सालाना की कीमत पर 10 लाख रुपए व 345 रुपए प्रति वर्ष पर 5 लाख रुपए रुपए दुर्घटना पॉलिसी की जाती है। जिसमे इस बीमा पालिसी में दुर्घटना मृत्यु,स्थायी विकलांगता आंशिक विकलांगता होने या घटना में अंग भंग होने या लकवा होने की स्थिति में दस लाख रुपए तक का क्लेम प्रदान किया जाता है। इस योजना को लेकर भारतीय डाक विभाग द्वारा जगह जगह डाक घरों में मेगा कैंप आयोजित किया जाता है जिससे यह सुविधा किसी भी नज्दीकी डाक घर में पोस्ट मेन द्वारा ली जा सकती है। ऐसे में आमजन

सके कि हड़ताल का कोई असर नहीं पड़ा है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से बीज निगम की पूरी व्यवस्था उन्हीं के भरोसे संचालित होती रही है। विपरीत परिस्थितियों में भी कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा से किया, लेकिन आज जब वे अपने अधिकार एवं सम्मान की मांग कर रहे हैं तो प्रबंधन दमनात्मक रवैया अपना रहा है। संघ की 2 प्रमुख मांगों में श्रम सम्मान निधि को पुनः प्रारंभ करना तथा वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रोजगार सुर्क्षा एवं उचित वेतनमान प्रदान करना शामिल है। कर्मचारियों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर सकायात्मक निर्णय नहीं लिया जाएगा, तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा।संघ ने शासन से मांग की है कि बीज निगम की वास्तविक स्थिति की निष्पक्ष जांच कराई जाए, फर्जी रिपोर्ट प्रस्तुत कर शासन को गुमराह करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए, ताकि कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों से राहत मिल सके।



अधिक से अधिक संख्या में अपने नज्दीकी डाक घर में संपर्क कर बीमा करवाकर लाभ ले।जिसके तहत ग्राम पंचायत मटका के डाक विभाग द्वारा पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत नंदलाल यदु की मृत्यु पश्चात उनकी पत्नी माया यदु को सौभष जोशी रीजनल मैनेजर रॉयल सुन्दरम बीमा कम्पनी के साथ रवि प्रसाद व बेमेतरा डाक विभाग के ब्रांच मैनेजर अभिषेक व मटका डाक विभाग के

सुशासन तिहार शिविर में उम्मीद ग्रामीणों की भीड़, सांसद भोजराज नाग व जिला पंचायत अध्यक्ष किरण नरेटी ने सुनी समस्याएं

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर /कांकेर:- दुर्गुकोदल विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सुरगंदोह में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं और मांगों को सुनने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शिविर में कांकेर सांसद भोजराज नाग एवं जिला पंचायत अध्यक्ष किरण नरेटी विशेष रूप से शामिल हुए। शिविर के दौरान कुल 37 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें बिजली, सड़क, स्टॉप डेम, पेयजल तथा अंदरूनी इलाकों में मोबाइल टॉवर जैसी प्रमुख समस्याएं शामिल रहीं। कार्यक्रम में 16 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण, सरपंच और सचिव उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए शीघ्र निराकरण का भरोसा दिलाया। सुशासन तिहार शिविर में हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी वितरित किया गया। राशन कार्ड आवेदकों को स्वीकृति प्रदान की गई, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास की चाबी एवं जमीन पट्टा वितरण किया गया। इस दौरान नवोदय विद्यालय की टॉपर छात्रा से मुलाकात कर जनप्रतिनिधियों ने उसे शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। शिविर में एसडीएम वाहिले भानुव्रतापपुर, तहसीलदार दुर्गुकोदल, जनपद सीईओ बंजारे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

आरोप है कि सड़क निर्माण में शासन के निर्धारित मापदंडों को ताक पर रख दिया गया है:बेस का अता-पता नहीं:- बिना उचित बेस तैयार किए

और बिना समतलीकरण के सीधे कांक्रीट बिछाया जा रहा है:मोटार्ड में भारी कटौती: सीसी रोड की जो मोटार्ड ड्राइंग-डिजाइन में होनी

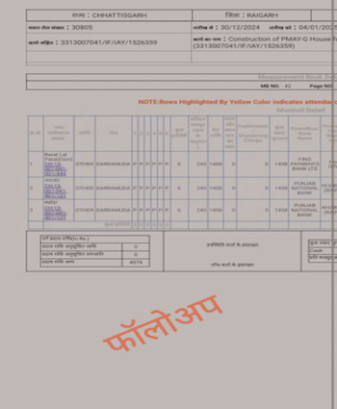
चाहिए, उसमें भारी हेराफेरी की जा रही है:घंटिया सामग्री का उपयोग: सीमेंट और रेत के अनुपात में गड़बड़ कर सिर्फ 'सफेद परत'

कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष बलदेव मण्डवी, सदस्य कामदेव बघेल, पदमनी कश्यप, जनपद अध्यक्ष रामवती भण्डारी, उपाध्यक्ष रितेश दास जोशी, योगेन्द्र कौशिक, बाबुल नाग, सुरेश गुप्ता, चन्दकान्त भण्डारी, जीवनाथ मौर्य, मुनिर कश्यप, कमल ठाकुर, विश्वनाथ कश्यप, रतुमा पोडियामी, सुरेश यादव, मासो पोडियामी, बसन्त कश्यप, सुमित्रा कश्यप, सरिता भोयर और बंक्क बघेल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी, कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ में सारांग-बिलाईगढ़ जिले एवं सकी जिले में निवासरत रामगामी समाज, जो अपनी अद्भुत साधना, आध्यात्मिक परंपरा और सारणीपूर्ण जीवनशैली के लिए देशभर में विशेष पहचान रखता है, ने एक बार फिर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने का कार्य किया है। रामगामी को जीवन का आधार मानने वाला यह समाज वर्षों से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखते हुए अपनी विशिष्ट परंपराओं के माध्यम से देश-दुनिया का ध्यान आकर्षित करता रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मुकाबलों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार इतने बड़े स्तर पर क्रिकेट और संस्कृति का ऐसा समारोह देखने को मिला, जहां खेल के साथ-साथ छत्तीसगढ़ की पारंपरिक पहचान को भी प्रयुक्त से प्रस्तुत किया गया। इस बार रायपुर को आईपीएल की प्रसिद्ध फ्रेंचाइजी Royal Challengers Bengaluru का होम ग्राउंड बनाया गया है। ऐसे में खिलाड़ियों के स्वागत, छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति के प्रदर्शन और प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को देश-दुनिया तक पहुंचाने के उद्देश्य से विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा किया गया, जिसमें सारांग-बिलाईगढ़, सकी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे रामगामी समाज के लोगों ने अपनी गरिमापूर्ण उत्पत्ति दर्ज कराई। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही रामगामी समाज के लोगों की पारंपरिक वेशभूषा ने सकी का ध्यान आकर्षित किया। सफेद वस्त्रों पर अंकित राम-नाम, सिर पर मोरपंखों से सजा मुकुट, शांत और आध्यात्मिक व्यक्तित्व तथा 'राम-राम' के अभिवादन ने आयोजन में एक अलग ही आध्यात्मिक वातावरण निर्मित कर दिया। कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों का पारंपरिक

पारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ल मीडिया प्रदेश सहप्रभारी एवं हिन्द युवा ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष दशक वैद्य ने 'सुशासन तिहार 2026' को कास का मध्यम' निरूपित करते हुए कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के ने में छत्तीसगढ़ सरकार गांव, ग्रामी अवदाता के द्वारा तप्त पहुंचकर सन का स्वर्णिम अथवा रच रही है। दशक वैद्य साहू ने कहा कि सुशासन के मध्यम में सुशासनी श्री विष्णु साय अनवरत रूप से गांव-गांव कर कामजन से आत्मीय सदापत कर रहे हैं। वे अनवदा भाइयों की खेत की मेड पर बैकुर सन रहे हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के 19 मई को प्रस्तावित जंगलरूप प्रवास को लेकर बस्तर में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। इस दौरान सर्व आदिवासी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल गृहमंत्री से सोझ-मुलाकात कर +नसल मुक्त बस्तर+ के लिए संतुलित और समावेशी विकास मॉडल का प्रस्ताव रखेगा। समाज का कहना है कि अब बस्तर को केवल सुरक्षा चुनौती नहीं, बल्कि देश के सामने आदिवासी नेतृत्व वाले विकास मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का समय आ गया है।



आशीष पदमवार। राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को बीजापुर जिले में रिकॉर्ड संख्या में मामलों का निराकरण किया गया। ट्रैप्टिक चालान, आवकारी, बैंक ऋण, बिजली बिल और राजस्व विवाद सहित 5 हजार से ज्यादा मामलों का आपसी समझौते के जरिए समाधान हुआ।